

सन २०१८-१९ करिता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय  
अन्न सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिकांकरिता  
(कापूस, ऊस) ₹ ३३५.५६६६६ लाख निधी  
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करणे.

**महाराष्ट्र शासन**

**कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग**

शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०१८/प्र.क्र.७७/४-अ

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक : २६ जून, २०१८

**वाचा:-**

१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२/०४/२०१८.
२. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि. १९/०४/२०१७.
३. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७/०४/२०१८.
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. No.२-९/२०१५ -CU-IV दि. ०३.०५.२०१८
५. कृषी आयुक्तालयाचे दि. २१.०५.२०१८ चे ई-मेल.
६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. अेअपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४-अ, दि. २३/०५/२०१८.

**प्रस्तावना:-**

केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत ऊस व कापूस या वाणिज्यिक पिकांवर आधारीत पिक पध्दतींचा समावेश केला असून, सदर अभियानाची केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पीकांच्या उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ करणे, शेत जमिनीची सुपीकता व उत्पादकता वाढविणे, रोजगारांची संधी निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे ही प्रमुख उद्दीष्टे आहेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान वाणिज्यिक पिकांकरीता संदर्भाधिन दि. २३ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ₹ ७९३.४० रकमेच्या कृती आराखड्यास प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या दिनांक १२ जून, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये अभियानाकरिता पहिल्या हप्त्यात ₹ २४८.८७ लक्ष निधी राज्यास प्राप्त झाला आहे, त्यापैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा ₹ २०१.३४ लक्ष व राज्य हिस्सा ₹ १३४.२२६६६ लक्ष असा एकूण ₹ ३३५.५६६६६ लक्ष निधी वितरणास उपलब्ध असून त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :-

**शासन निर्णय:**

१. सन २०१८-१९ करिता कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरीता (कापूस, ऊस) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्साचा एकूण ₹ ३३५.५६६६६ लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी पस्तीस लाख छप्पन्न हजार सहाशे सहासष्ट फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांना अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे अभियानांतर्गत वाणिज्यिक

पिकांकरीता (कापूस, ऊस) या पिकांकरीता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, सदर निधीचे केंद्र व राज्य हिस्श्याचे पिकनिहाय विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:-

(₹ लाख)

| अ. क्र. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत वाणिज्यिक पिके | सर्वसाधारण प्रवर्ग  |                    | एकूण वितरीत निधी |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|         |                                                      | केंद्र हिस्सा (६०%) | राज्य हिस्सा (४०%) |                  |
| १.      | कापूस                                                | ६९.८६               | ४६.५७३३३           | ११६.४३३३३        |
| २.      | ऊस                                                   | १३१.४८              | ८७.६५३३३           | २१९.१३३३३        |
|         | एकूण                                                 | २०१.३४              | १३४.२२६६६          | ३३५.५६६६६        |

२. परिच्छेद-१ मध्ये नमूद केल्यानुसार कापूस या पिकाकरिता केंद्र हिस्श्याचा ६९.८६ लक्ष निधी (अक्षरी रुपये एकोणसत्तर लाख शहाऐंशी हजार फक्त) आणि राज्य हिस्श्याच्या ₹ ४६.५७३३३ लक्ष निधी (अक्षरी रुपये सेहचाळीस लक्ष सत्तावन्न हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) असा एकूण रु. ११६.४३३३३ लक्ष (रुपये एक कोटी सोळा लाख त्रेचाळीस हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे.

३. परिच्छेद-१ मध्ये नमूद केल्यानुसार ऊस या पिकाकरिता केंद्र हिस्श्याचा ₹ १३१.४८ लक्ष निधी (अक्षरी रुपये एक कोटी एकतीस लाख अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) आणि राज्य हिस्श्याच्या ₹ ८७.६५३३३ लक्ष निधी (अक्षरी रुपये सत्याऐंशी लक्ष पासष्ट हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) असा एकूण ₹ २१९.१३३३३ लक्ष (रुपये दोन कोटी एकोणीस लाख तेरा हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे.

४. परिच्छेद-१ ते ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार, ऊस, कापूस पिकाकरिता अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत केलेला केंद्र निधी सन २०१८ -१९ मध्ये पुढील लेखाशिर्षाखालील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्ची टाकावा:-

| केंद्र/राज्य हिस्सा | लेखाशिर्ष                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | कापूस                                                                                                                                                                                                                          | ऊस                                                                                                                                                                                                                          |
| केंद्र हिस्सा       | <b>मागणी क्रमांक डी-३</b><br>२४०१- पीक संवर्धन<br>१०८, वाणिज्यिक पिके<br>(०१) (०२) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस (केंद्र हिस्सा ६०%)<br>(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ २५४२)<br>(योजनांतर्गत) (दत्तमत)<br>३३, अर्थसहाय्य | <b>मागणी क्रमांक डी-३</b><br>२४०१- पीक संवर्धन<br>१०८, वाणिज्यिक पिके<br>(०२) (०८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- ऊस (केंद्र हिस्सा ६०%)<br>(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ४०५१)<br>(योजनांतर्गत) (दत्तमत)<br>३३, अर्थसहाय्य |

|              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राज्य हिस्सा | मागणी क्रमांक डी-३<br>२४०१- पीक संवर्धन<br>१०८, वाणिज्यिक पिके<br>(०१) (१६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-<br>कापूस (राज्य हिस्सा ४०%)<br>(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ A२५२)<br>(योजनांतर्गत) (दत्तमत)<br>३३, अर्थसहाय्य | मागणी क्रमांक डी-३<br>२४०१- पीक संवर्धन<br>१०८, वाणिज्यिक पिके<br>(०२) (११) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा<br>अभियान- ऊस (राज्य हिस्सा ४०%)<br>(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ A२४३)<br>(योजनांतर्गत) (दत्तमत)<br>३३, अर्थसहाय्य |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

५. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरिता )कापूस,ऊस (उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या ₹ ३३५.५६६६६ लक्ष रक्कमेचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हा निहाय वाटप करावयाचा निधी PFMS प्रणालीद्वारे सर्व संबंधित जिल्ह्यांना वितरीत करावा.
६. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या ₹ ३३५.५६६६६ लक्ष निधीचे विविध कार्यालयांच्या स्तरावर कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता खालील अधिकाऱ्यांना त्या-त्या स्तरावर नियंत्रण अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:-

| अ. क्र. | कार्यालय                    | नियंत्रण अधिकारी                                   | आहरण व संवितरण अधिकारी                                                |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| १.      | कृषी आयुक्तालय              | संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे | सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे                           |
| २.      | जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी | जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी                        | संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी |

७. केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ करिता वार्षिक कृती आराखड्यास संदर्भाधीन दि.२३ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी अभियानाकरिता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहिल, याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे.
८. संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी / तालुका कृषि अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरिता लाभार्थ्यांची निवड करून अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची

यादी तालुका स्तरावर संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबींची माहिती संकलित करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची राहिल.

९. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विविध घटकांतर्गत लाभार्थी शेतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे, त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सर्व घटकांखाली 'आधार क्रमांकाशी' सांगड घालून थेट लाभार्थ्यांच्या खाती अनुदान जमा करण्याची (Direct Benefit Transfer) कार्यवाही करावी.
१०. उन्नत शेती -समृद्ध शेतकरी या मोहिमेच्या संदर्भाधीन दि.२७ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तसेच, लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाबाबत (DBT) संदर्भाधीन दि. १९ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांतर्गत विविध घटकांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करावी याबाबत मार्गदर्शक सूचना विहित केलेल्या आहेत. सदर दोन्ही शासन निर्णयातील सूचनांनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत-वाणिज्यिक पिकांच्या सर्व घटकांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
११. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या शेतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषी सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे कृषी सहायकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे.
१२. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल.
१३. केंद्र सहाय्यीत योजनकरिता निधी वितरणासाठी वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२ एप्रिल, २०१८नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे.

सदर शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२६१३३००११००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(श्रीकांत चं. आंडगे)  
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति:-

१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
८. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला.
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे.
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक
१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी
१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई.
१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर
१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य
१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे
१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई
२०. निवड नस्ती-४अ